मुंबई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
हर खबर निष्पक्षता के साथ
मुंबई
वर्षः 9 अंक 09
मंगलवार, 14 जुलाई 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

राम मंदिर चंदा चोरीः सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भेजा नोटिस, एसआईटी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली, 13 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान की कथित चोरी की निष्पक्ष और तय समय-सीमा के भीतर जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दान की कथित चोरी के मामले में अपनी जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र और राज्य की ओर से पेश हुए, ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, जब कोर्ट याचिकाओं पर विचार करेगा और SIT की जांच के नतीजों की समीक्षा करेगा। तीन याचिकाकताओं में से एक, नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की CBI जांच की मांग की। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की उअऋ (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) से ऑडिट कराने की भी मांग की; यह ट्रस्ट राम मंदिर के कामकाज का प्रबंधन करता है। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने भी ऐसी ही मांग करते हुए दूसरी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग के अलावा, RJD सांसद सुधाकर सिंह द्वारा

दायर तीसरी याचिका में मंदिर ट्रस्ट के पूरे वित्तीय कामकाज की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की गई है।

जून के पहले हफ़्ते में राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आने पर मंदिर के दान के कथित दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया। मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। SIT में लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस और स्पेशल सेक्रेटरी (फाइनेंस) नील रतन शामिल हैं। SIT को गबन के शुरूआती सबूत मिले, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। अब तक, इस मामले में मंदिर की दान-गिनती प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। SIT के अनुसार, 45 दिनों की CCTV फुटेज में इन प्रक्रियाओं का बार-बार उल्लंघन देखा गया।

जांचकताओं का आरोप है कि आरोपियों ने गिनती हॉल के अंदर कैश की आवाजाही पर कमजोर निगरानी और अपर्याप्त जांच का फायदा उठाया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान कम से कम 70 बार चोरी हुई। इसमें जांच से पहले कुछ कर्मचारियों से लगभग 78.94 लाख रुपये और गिनती वाले कमरे से जुड़े बाथरूम से 2.25 लाख रुपये बरामद होने का भी ज़िक्र है।

ईरान का 'जैसे को तैसा' : मिसाइल-ड्रोन से दहल उठे खाड़ी देश

तेहरान। पश्चिम एशिया में पिछले चार महीनों से जारी संघर्ष अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ दिनों पहले तक जिस शांति वार्ता से उम्मीद की किरण दिख रही थी, वह अमेरिका और ईरान के बीच 'शर्तें न मानने' के आरोपों की भेंट चढ़ गई। ऐसे में शांति की कोशिशें थमते ही दोनों देशों के बीच भीषण हमलों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है।

इसी बीच, ईरान की सेना 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (क्म्क्ष्ठ) ने सोमवार को एक सनसनीखेज दावा करके वैश्विक राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। क्म्क्ष्ठ का कहना है कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से तीन चरणों में बड़ा हमला किया है। ईरान ने इस सैन्य कार्रवाई को 'जैसे को तैसा' नाम दिया है। हालांकि, ईरान के इन दावों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।

ईरानी मीडिया के अनुसार, यह हमला पिछले 48 घंटों से अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद किया गया। क्म्क्ष्ठ ने हमले को तीन चरणों में बांटकर अंजाम देने का दावा किया है।

पहला चरण में ईरान के द्वारा जॉर्डन को निशाना बनाया गया। दावा है कि ईरान ने जॉर्डन के 'प्रिंस हसन एयरबेस' पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे वहां मौजूद ईंधन डिपो और गोला-बारूद के गोदामों में आग लग गई। दूसरे चरण के तहत ईरान ने बहरीन के 'शेख ईसा एयरबेस' को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक, यहाँ अमेरिकी हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर, पी-8 विमान के हैंगर और ड्रोन कमांड सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं तीसरा चरण के तहत ईरानी सेना ने कुवैत के 'अली अल-सालेम एयरबेस' पर हमला कर अमेरिकी 'पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम' और ईंधन टैंकों को तबाह करने का दावा किया गया है।

वियतनाम नाव हादसाः मुंबई लाए गए 15 भारतीयों के शव, लावा परिवार को देगी 25-25 लाख रुपये की सहायता

मुंबई, 13 जुलाई। वियतनाम के फू क्वेक द्वीप के पास स्पीडबोट हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर सोमवार देर रात विशेष विमान से मुंबई लाए गए। वियतनाम एयरलाइंस की विशेष उड़ान (वीएन-979) हो ची मिन्ह सिटी से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। मृतकों में 10 तमिलनाडु, तीन आंध्र प्रदेश और दो केरल के निवासी थे। पार्थिव शरीरों को उनके गृह राज्यों के लिए भेजा जा रहा है। वहीं, एक पर्यटक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज हो ची मिन्ह सिटी के अस्पताल में चल रहा है।

यह हादसा शुक्रवार को उस समय हुआ था, जब 32 भारतीय पर्यटकों और चार स्थानीय क्रू सदस्यों को लेकर जा रही स्पीडबोट फू क्वेक के एन थोई द्वीप समूह के पास अचानक पलट गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। गंभीर रूप से घायल 49 वर्षीय पर्यटक के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा है, मस्तिष्क में रक्तस्त्राव हुआ है और उसका इलाज जारी है। भारतीय दूतावास उसके इलाज की निगरानी कर रहा है। हादसे में शामिल पर्यटक भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा इंटरनेशनल के प्रायोजन पर वियतनाम गए थे। कंपनी ने मृतकों के स्वजनों को 25-25 लाख रुपये की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार, उसके 86 कर्मचारी और बिजनेस पार्टनर इस यात्रा पर गए थे। अधिकांश लोग भारत लौट आए हैं, जबकि कुछ लोग वियतनाम में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए रुके हुए हैं।

हाई कोर्ट ने रेलवे को दी नसीहतः सब्जियों की तरह बिक रही हैं ट्रेन की खाली सीटें, दोषी टीटीई पर करें कार्रवाई

कोलकता, 13 जुलाई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ 'यात्रा टिकट परीक्षक' (टीटीई) रेलगाड़ियों में खाली बर्थ को "बाजार में सब्जियों की तरह बेचते हैं।" अदालत ने देश के सभी रेलवे मंडलों के महाप्रबंधकों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में दोषी टीटीई के खिलाफ उपलब्ध अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी ही एक घटना के कारण मादक पदार्थ देकर दो यात्रियों से लूटपाट की गयी और मादक पदार्थ के कारण ही उनमें से एक यात्री की मौत हो गयी।

अदालत ने कहा कि फरवरी 2009 में न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रही तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में दो व्यक्ति अनारक्षित टिकट लेकर सवार हुए थे। उन्होंने टीटीई को रिश्वत देकर बर्थ हासिल की। बाद में दो अपराधियों ने उनके कीमती सामान लूटने के इरादे से उन्हें नशीला पदार्थ दे दिया। इनमें से एक यात्री की उसे दिए गए नशीले पदार्थ के कारण मौत हो गयी। उसे पहले से अन्य गंभीर बीमारियां थीं।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने कहा, "यह अदालत इस फैसले की प्रति पूर्वी रेलवे सहित देश के सभी रेलवे मंडलों के महाप्रबंधकों को भेज रही है, ताकि ट्रेन की खाली बर्थ को बाजार में सब्जियों की तरह बेचने वाले टीटीई के खिलाफ उपलब्ध अधिकतम दंड सुनिश्चित किया जा सके।" अदालत ने कहा कि टीटीई के इस आचरण के कारण एक ऐसे यात्री की जान चली गई, जिससे केवल लूटपाट की गयी थी।खंडपीठ ने कहा, "ऐसे कई मामले हैं, जिनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती, लेकिन उनमें मामूली चोरी के शिकार लोगों को गंभीर चिकित्सकीय परिणाम भुगतने पड़ते हैं।" खंडपीठ ने पिछले सप्ताह दिए आदेश में कहा कि ऐसे अपराधों के लिए टीटीई की भूमिका ही मूल कारण बनती है। अदालत ने जांच और अभियोजन में कई गंभीर खामियों को लेकर पुलिस की भी कड़ी आलोचना की। इस मामले में आलोक घोष और गोपाल मिस्त्री को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 328 के तहत जहर या नशीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाने, चोरी करने तथा जीवित बचे यात्री की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा अन्य सजाएं सुनाई थीं। सभी सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि घोष और मिस्त्री क्रमशः 10 और 16 वर्ष जेल में बिताने के बाद फिलहाल जमानत पर हैं। आलोक घोष और गोपाल मिस्त्री को 10 जुलाई 2017 को दोषी ठहराया गया था और अगले दिन सियालदह सत्र अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले की जांच अपर्याप्त रही। अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने मृतक की विसरा की फॉरेंसिक रिपोर्ट तक प्राप्त नहीं की। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि विसरा को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया था।

भूपेश बघेल ने बीजेपी-आरएसएस पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 13 जुलाई। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सोमवार को आरोप लगाया कि BJP और RSS एक तरफ वोटों की चोरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता से मिले दान की चोरी कर रहे हैं। उनके ये बयान राम मंदिर के लिए मिले दान की चोरी के आरोपों के बीच आए हैं। उन्होंने यहाँ पत्रकारों से कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने अयोध्या राम तीर्थ क्षेत्र के लिए मिले दान और चढ़ावे की चोरी के मामले में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आपको 'रामशिला पूजा' कार्यक्रम याद होंगे; BJP और RSS के सदस्यों ने देश भर के गाँवों का दौरा किया और करोड़ों रुपये इकट्ठा किए। आज तक उस पैसे का कोई हिसाब-किताब नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो लोगों ने फिर से दान दिया। छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों ने करोड़ों रुपये का दान दिया; हालाँकि, निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें सामने आई हैं, खासकर यह आरोप कि 40%

कमीशन लिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने भी राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। राजनीति

सदन में मुझसे पूछा गया कि क्या मैंने, यानी भूपेश बघेल ने भी दान दिया है। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैंने दिया था और वह रकम 1,21,000 रुपये थी। मेरी तरह ही लाखों लोगों ने निर्माण में योगदान दिया... इसीलिए हम सदन में इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भगवान राम को भी नहीं बख्श रहे हैं; वे एक तरफ वोटों की चोरी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धार्मिक चढ़ावे की चोरी। भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग ऐसा कर रहे हैं।

यूपी को नितिन गडकरी की सौगात, 60,000 करोड़ रुपये के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

लखनऊ, 13 जुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के लिए 50,000-60,000 करोड़ रुपये के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें उत्तर-दक्षिण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। 4,850

करोड़ रुपये से ज्यादा के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि नई मंजूरियों में पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए बाईपास और राज्य के हर ज़िला मुख्यालय तक चार-लेन कनेक्टिविटी शामिल है। आदित्यनाथ ने कहा कि आज गडकरी ने 50,000-60,000 करोड़ रुपये के रोड प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए पहले से ही बेहतरीन ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी है, लेकिन अब नॉर्थ-साउथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नए इलाकों की पहचान की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए बाईपास और राज्य के हर ज़िला मुख्यालय तक फोर-लेन कनेक्टिविटी को भी मंजूरी दी है। गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मंजूरियों से उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क मजबूत होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में राज्य में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दस साल पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। न तो कोई नीति थी और न ही कोई दिशा।

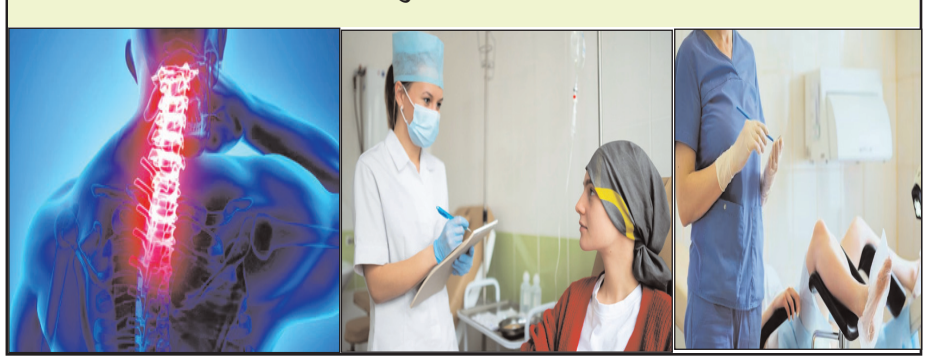

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

TIWARI'S SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
✓ 34+ Years of Academic Excellence
✓ Experienced & Dedicated Faculty
✓ Personal Attention
✓ Printed Notes & Regular Tests
✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055
Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
• Std. XI & XII (Sci.)
• NEET
• JEE (Main & Advance)
• MHT-CET
• Polytechnic & Engg
• Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

अमेरिका-ईरान टकराव और विश्व शांति की नई चुनौती

-ललित गर्ग

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद बड़ी कठिनाई से बना संघर्ष विराम अपनी निर्धारित अवधि पूरी करने से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच गया है। ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए ताजा हमलों और उसके जवाब में अमेरिका की भीषण बमबारी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को युद्ध की आशंकाओं के बीच खड़ा कर दिया है। यह केवल दो देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता और मानवीय मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है। जिस समय विश्व को महामारी, आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना चाहिए, उस समय महाशक्तियों का युद्धोन्माद पूरी मानवता को पीछे धकेलने का कार्य कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न विवाद ने इस संघर्ष को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। विश्व के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो केवल तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटेंगी और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होगी। युद्ध की आग कभी सीमाओं में नहीं रहती, उसकी तपिश अंततः पूरी दुनिया को झुलसाती है।

इस संघर्ष का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसमें निर्दोष नागरिकों, नाविकों और आम जनजीवन को सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। हाल के घटनाक्रम में भारतीय नाविकों के प्रभावित होने और भारत के सहयोग से विकसित रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह परियोजना को नुकसान पहुंचने से यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक विश्वास-तीनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमेरिका स्वयं को लोकतंत्र और विश्व व्यवस्था का संरक्षक बताता है, लेकिन उसकी विदेश नीति लंबे समय से प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित रही है। किसी भी राष्ट्र को झुकाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य हमले और राजनीतिक दबाव स्थायी समाधान नहीं हो सकते। महाशक्ति होने का अर्थ केवल सैन्य सामर्थ्य नहीं, बल्कि संयम, दूरदृष्टि और विश्व समुदाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यदि शक्ति विवेक से संचालित न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।

दूसरी ओर ईरान को भी यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को अपने रणनीतिक हितों के लिए बंधक बनाना न तो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और न ही वैश्विक विश्वास के अनुकूल। किसी भी देश की सुरक्षा तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के साथ सहयोग, विश्वास और पारदर्शिता का वातावरण निर्मित न करे। भय और प्रतिशोध पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था अंततः स्वयं को ही असुरक्षित बना देती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली ने इस पूरे संकट को और अधिक अनिश्चित बनाया है। एक ओर वे कठोर सैन्य कार्रवाई करते हैं, दूसरी ओर वार्ता और समझौते की बातें करते हैं। इस प्रकार के विरोधाभासी संदेश न केवल कूटनीतिक विश्वास को कमजोर करते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अस्थिरता पैदा करते हैं। महाशक्तियों के नेताओं के प्रत्येक वक्तव्य का प्रभाव केवल उनके देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था, निवेश, ऊर्जा बाजार और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए नेतृत्व में धैर्य, स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है।

इतिहास गवाह है कि युद्धों ने कभी स्थायी समाधान नहीं दिया। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया तक, हर युद्ध ने नई समस्याएं ही पैदा की हैं। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लेकिन अंततः समाधान फिर बातचीत की मेज पर ही खोजे गए। यदि अंत में संवाद ही करना है, तो शुरूआत भी संवाद से ही क्यों नहीं हो सकती? यही प्रश्न आज पूरी मानवता के सामने खड़ा है। भारत ने सदैव विश्व को शांति, सह-अस्तित्व और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी की भूमि ने यह सिखाया कि वास्तविक विजय शत्रु को पराजित करने में नहीं, बल्कि शत्रुता को समाप्त करने में है। भारत की विदेश नीति भी ह्यवसुधैव कुटुम्बकम्ह और ह्यविश्वबंधुत्वह्व के आदर्शों पर आधारित रही है। भारत ने हमेशा संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही कारण है कि भारत आज विश्वसनीय मध्यस्थ, संतुलित शक्ति और जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में सम्मान प्राप्त कर रहा है।

वर्तमान संकट में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के साथ संतुलित संबंध हैं। भारत यदि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सक्रिय शांति पहल करे, तो तनाव कम करने में उसकी भूमिका प्रभावी सिद्ध हो सकती है। साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी। आज आवश्यकता किसी एक पक्ष की विजय की नहीं, बल्कि मानवता की विजय की है। हथियारों की होड़ से न तो समृद्धि आती है और न ही सम्मान। वास्तविक शक्ति मिसाइलों, बमों और युद्धपोतों में नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और संवाद में निहित होती है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वह केवल नई समस्याओं को जन्म देता है। अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि आत्मबल, धैर्य और दूरदर्शिता का सर्वोच्च स्वरूप है।

विश्व समुदाय को अब यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि किसी भी देश की मनमानी, सामरिक अहंकार और युद्धोन्माद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संस्थाओं को अधिक प्रभावी, निष्पक्ष और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यदि आज भी दुनिया ने युद्ध की राजनीति पर अंकुश नहीं लगाया, तो भविष्य की पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। आज पूरी दुनिया की प्रार्थना यही है कि अमेरिका को शक्ति के साथ सद्बुद्धि मिले, ईरान को संयम और विवेक का मार्ग मिले तथा दोनों राष्ट्र हथियारों की भाषा छोड़कर संवाद की संस्कृति अपनाएं। शांति ही विकास का आधार है, संवाद ही स्थायी समाधान का मार्ग है और अहिंसा ही मानव सभ्यता का सबसे बड़ा अस्त्र है। यही समय की पुकार है, यही मानवता की अपेक्षा है और यही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भी।

इतिहास की भूलों का परिमार्जन और नया नौसैनिक विजन

अशोक भाटिया

इतिहास गवाह है कि जो राष्ट्र अपनी समुद्री सीमाओं की अनदेखी करता है, उसकी संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि हमेशा खतरे में रहती है। भारत, चोल साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज की महान नौसैनिक विरासत का उत्तराधिकारी होने के बावजूद, आजादी के बाद के कई दशकों तक एक 'महाद्वीपीय मानसिकता' का शिकार रहा। हमारी रक्षा नीतियों का झुकाव मुख्य रूप से स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित रहा और नौसेना को वह रणनीतिक प्राथमिकता नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस दृष्टिकोण में एक युगांतरकारी और मौलिक बदलाव आया। पिछले एक दशक (2014-2024 और उसके बाद) में भारतीय नौसेना ने न केवल अपनी परिचालन क्षमता का विस्तार किया है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और रणनीतिक पहचान का भी पुनरुद्धार किया है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्पों पर सवार होकर आज भारतीय नौसेना हिंद महासागर से लेकर इंडो-पैसिफिक के सुदूर छोर तक वैश्विक व्यवस्था की एक अपरिहार्य और निर्णायक शक्ति बन चुकी है। समुद्र की लहरों पर दौड़ती इसी अदम्य भारतीय शक्ति को आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ सलाम कर रही है।

गौरतलब है कि एक दशक पहले तक भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में होती थी। जटिल सैन्य उपकरणों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर हमारी निर्भरता रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक बड़ा खतरा थी। संकट के समय विदेशी ताकतों द्वारा कलपुर्जों की आपूर्ति रोकने का जोखिम हमेशा बना रहता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी कमजोरी पर प्रहार करते हुए नौसेना को ह्यबिल्डर नेवीह (में बदलने का स्पष्ट रोडमैप दिया प्रोजेक्ट 17ए और अन्य अत्याधुनिक रक्षा परियोजनाओं के तहत आइएनएस महेंद्रगिरी, आइएनएस दूनागिरि, आइएनएस संशोधक, और आइएनएस अंजे जैसे गाइडेड-मिसाइल और स्टील्थ युद्धपोतों का घरेलू शिपयार्ड्स में निर्माण भारत की बदलती औद्योगिक और तकनीकी क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये केवल स्टील के तैरते हुए ढांचे नहीं हैं; ये भारत में ही विकसित उन्नत रडार, सोनार, अत्याधुनिक सेंसर और ब्रह्मोस जैसी अचूक मिसाइल प्रणालियों से लैस आधुनिक तैरते हुए अभेद्य किले हैं।

माझगांव डॉक, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और कोचीन शिपयार्ड जैसी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया। आज इन शिपयार्ड्स के पास एक साथ दर्जनों युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण की क्षमता है। परिणाम यह है कि वर्तमान में नौसेना के भावी बेड़े में शामिल होने वाले युद्धपोतों में स्वदेशीकरण का स्तर 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) में किए गए नीतिगत सुधारों ने देश के भीतर एक मजबूत रक्षा इकोसिस्टम तैयार किया है। हजारों लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) और टेक स्टार्ट-अप्स आज नौसेना के लिए विश्व स्तरीय कलपुर्जे और सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं, जिससे देश का पैसा देश के भीतर ही रह रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

भारतीय नौसेना के आधुनिक इतिहास में 2 सितंबर 2022 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। इस दिन देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत केवल एक सैन्य जहाज नहीं है, बल्कि यह इक्कीसवीं सदी के भारत के सामर्थ्य, कौशल और राष्ट्रीय संकल्प का चमकता हुआ प्रतीक है।

इस विशाल फ्लोटिंग एयरफील्ड के निर्माण के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा 5-6 देशों के विशिष्ट और संभ्रांत क्लब में शामिल हो गया, जो 40,000 टन से अधिक वजनी और अत्याधुनिक विमानवाहक पोतों को पूरी तरह से खुद डिजाइन और निर्मित करने की क्षमता रखते हैं।

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ा रणनीतिक और सांस्कृतिक कदम उठाया। नौसेना के ध्वज से औपनिवेशिक गुलामी के प्रतीक 'सेंट जॉर्ज क्रॉस' को हमेशा के लिए हटा दिया गया और उसकी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्र से प्रेरित नए नौसैनिक ध्वज (निशान) का अनावरण किया गया। यह कदम इस बात का उद्घोष था कि नया भारत अब अपनी सुरक्षा रणनीतियां और अपनी पहचान विदेशी चश्मे से नहीं, बल्कि अपनी गौरवशाली विरासत के आधार पर तय करेगा। हिंद महासागर क्षेत्र दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। दुनिया की कुल ऊर्जा आपूर्ति और वाणिज्यिक जहाजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता, पनडुब्बियों की अनधिकृत आवाजाही और उसकी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति ने एक बड़ा असंतुलन पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन भारत ने अपनी मजबूत नौसैनिक उपस्थिति से चीन की इस घेराबंदी को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश और रक्षा नीति का मूल मंत्र सागर और हालिया महासागर दृष्टिकोण है। यह विजन स्पष्ट करता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक आक्रामक शक्ति नहीं, बल्कि एक समावेशी और सहयोगी शक्ति है, जो सभी पड़ोसी मित्र देशों की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति को अपनी प्रगति से जोड़कर देखता है।

पिछले कुछ वर्षों में अदन की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर सोमाली डाकुओं के आतंक और ड्रोन हमलों में अचानक भारी वृद्धि देखी गई। जब दुनिया की कई बड़ी नौसेनाएं इस संकट के सामने असहाय या रक्षात्मक मुद्रा में थीं, तब भारतीय नौसेना ने 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की भूमिका निभाते हुए कड़ा रुख अपनाया। नौसेना के विशेष कमांडो ने रात के अंधेरे में बीच समुद्र में कई साहसिक ऑपरेशन चलाए। उन्होंने न केवल भारतीय जहाजों को बचाया, बल्कि बुल्गारिया, पाकिस्तान, ईरान और अन्य देशों के अपहत जहाजों और उनके चालक दल के सदस्यों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला। बुल्गारिया के राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए भारत सरकार और नौसेना का सार्वजनिक आभार व्यक्त करना इस बात का प्रमाण है कि आज पूरी दुनिया भारत की इस वैश्विक भूमिका को सलाम कर रही है।

किसी भी देश को वैश्विक महाशक्ति का दर्जा तब तक प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक कि उसके पास जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों से परमाणु हमले का मुकाबला करने की अचूक क्षमता न हो। इसे रक्षा की भाषा में 'न्यूक्लियर ट्रायाड' कहा जाता है। पिछले दस वर्षों में भारत ने समुद्र के नीचे अपनी 'सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी' को अत्यंत अभेद्य और विश्वसनीय बनाया है।

भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आइएनएस अरिहंत और उसके बाद उन्नत संस्करण आइएनएस अरिघात की सफल तैनाती ने देश की रणनीतिक कूटनीति को एक नई ऊंचाई दी है। ये परमाणु पनडुब्बियां समुद्र की अगाध गहराइयों में महीनों तक बिना भनक लगे छिपी रह सकती हैं और दुश्मन के किसी भी दुस्साहस या पहले परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी परमाणु हमला करने की अचूक क्षमता रखती हैं। स्कॉर्पीन श्रेणी की अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों (जैसे आईएनएस कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर) के बेड़े ने भारतीय नौसेना की खुफिया और स्टील्थ मारक क्षमता को दुश्मन के तटीय क्षेत्रों के बेहद करीब तक पहुंचा दिया है। ये पनडुब्बियां समुद्र के नीचे भारत की आंख और कान बनकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं।

इक्कीसवीं सदी के आधुनिक युद्ध केवल पारंपरिक तोपों, गोलों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता , साइबर स्पेस और इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारतीय नौसेना को 'नेट-सेंट्रिक वॉरफेयर' यानी सूचना-केंद्रित युद्ध प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी सुधार किए गए हैं।

नौसेना के समर्पित सैन्य उपग्रहों जीएसएटी श्रृंखला की मदद से आज भारत वास्तविक समय में पूरे हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रख रहा है। समुद्री क्षेत्र जागरूकता के तहत गुरुग्राम में स्थापित 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर' आज दुनिया के दर्जनों देशों के साथ रीयल-टाइम डेटा साझा करता है, जिससे समुद्र में होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

इसके अतिरिक्त, अमेरिकी प्रीडेटर एम क्यू 9इ सी गार्जियन ड्रोन्स की रणनीतिक खरीद और घरेलू स्तर पर 'स्वावलंबन' जैसी पहलों के माध्यम से मानवरहित प्रणालियों स्वायत्त जहाजों और एंटी-ड्रोन जैमर्स को शामिल कर नौसेना ने खुद को भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है।

स्पष्ट है कि आज भारतीय नौसेना केवल युद्ध की तैयारी करने वाला बल नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति का सबसे मजबूत और चमकीला माध्यम बन चुकी है।

अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी वैश्विक महाशक्तियों के साथ मिलकर किया जाने वाला 'मालाबार युद्धाभ्यास' और भारत द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय 'मिलन' युद्धाभ्यास, जिसमें दुनिया के 50 से अधिक देश शामिल होते हैं, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने की भारत की केंद्रीय भूमिका को प्रदर्शित करता है।चाहे तुर्की या नेपाल में आया विनाशकारी भूकंप हो, यमन और सूडान के गृहयुद्ध के बीच से विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना हो, या कोविड-19 महामारी के दौरान मित्र देशों तक 'मिशन सागर' के तहत दवाएं और ऑक्सीजन पहुंचाना हो—भारतीय नौसेना हमेशा संकटमोचक बनकर सबसे आगे खड़ी रही है। भारत की इसी मानवीय और पराक्रमी कूटनीति का परिणाम है कि आज दुनिया का हर मंच भारत की नौसैनिक शक्ति को वैश्विक शांति का आधार मानता है।

प्रसिद्ध नौसैनिक रणनीतिकार अल्फ्रेड थायर महान ने कहा था, ₹जिस राष्ट्र का समुद्र पर नियंत्रण होगा, वही दुनिया की नियति और अर्थव्यवस्था को तय करेगा।₹ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शाश्वत सत्य को समय रहते पहचाना और भारतीय नौसेना को नीतिगत प्राथमिकताओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया।आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, तब देश का 95 प्रतिशत व्यापार (मात्रा के अनुसार) और 65 प्रतिशत व्यापार (मूल्य के अनुसार) समुद्र के रास्ते ही संपन्न होता है। ऐसे में एक शक्तिशाली, आधुनिक और आत्मनिर्भर नौसेना देश की आर्थिक समृद्धि और विकास का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

पिछले दस-बारह वर्षों का यह स्वर्णिम सफर इस बात का जीवंत साक्ष्य है कि भारतीय नौसेना अब केवल अपनी मुख्य भूमि की रक्षा करने वाला बल नहीं है; बल्कि यह वैश्विक शांति, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कूटनीति की मार्गदर्शक बन चुकी है। समुद्र की नीली लहरों की छाती को चीरकर दौड़ती भारत की यह नौसैनिक शक्ति आज दुनिया के सामने यह उद्घोष कर रही है कि इक्कीसवीं सदी का भारत अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और वैश्विक शांति का सबसे मजबूत स्तंभ है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारतीय नौसेना के इस पराक्रम और देश के दृढ़ नेतृत्व को झुककर सलाम कर रही है।

क्या न्यायपालिका पर घट रहा है जनविश्वास?

– महेन्द्र तिवारी

आज के समय में न्यायपालिका केवल संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों के अंतिम विश्वास का केंद्र भी है। जब कार्यपालिका और विधायिका से किसी व्यक्ति को राहत नहीं मिलती, तब उसकी अंतिम उम्मीद न्यायालय से जुड़ती है। ऐसे में यदि सर्वोच्च न्यायालय के भीतर ही ऐसी घटना घटे जिसमें एक याचिकाकर्ता न्यायाधीशों को ₹ज्यूडिशियल सर्वेंट₹ कहकर संबोधित करे, स्वयं को ₹सॉवरेन₹ घोषित करे, न्यायालय को आदेश देने की भाषा बोले, कागज हवा में उछाल दे और मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे, तो यह केवल एक व्यक्ति का अनुचित व्यवहार नहीं रह जाता। यह घटना न्यायपालिका, समाज और लोकतंत्र के संबंधों पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं पैरवी कर रहे प्रबल प्रताप द्वारा ऐसा व्यवहार किए जाने के बाद अदालत की कार्यवाही बाधित हुई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर ले जाकर स्थिति को सामान्य किया। यह घटना देशभर में चर्चा का विषय बन गई। इस घटना को देखने के दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहला यह कि यह पूरी तरह से न्यायालय की अवमानना और लोकतांत्रिक मयार्दाओं का उल्लंघन है। दूसरा यह कि यह उस गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति है जो वर्षों से लंबित मामलों और न्याय मिलने में होने वाली देरी के कारण समाज के एक वर्ग में पनप रहा है। दोनों दृष्टिकोणों को समझे बिना इस घटना का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव नहीं है। भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक है। देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। अनेक मामलों में न्याय पाने में वर्षों नहीं बल्कि दशकों का समय लग जाता है। कई बार मुकदमे की शुरूआत करने वाला व्यक्ति अंतिम निर्णय देखने के लिए जीवित भी नहीं रहता। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां अगली पीढ़ी मुकदमा लड़ती रहती है। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से लोगों में निराशा पैदा करती है। प्रसिद्ध कहावत है कि विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करने के समान होता है। जब नागरिकों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो रहा, तब व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। यही कमजोर होता विश्वास कभी-कभी आक्रोश का रूप भी ले लेता है।

लेकिन क्या यह आक्रोश अदालत के भीतर अनुशासन तोड़ने का अधिकार दे देता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। न्यायिक निर्णयों की आलोचना भी की जा सकती है। पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। संविधान ने इसके अनेक कानूनी रास्ते दिए हैं। किंतु न्यायालय के भीतर न्यायाधीशों को आदेश देना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या कार्यवाही बाधित करना किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। यदि हर व्यक्ति स्वयं को सर्वोच्च मानकर अदालत को निर्देश देने लगे, तो कानून का शासन समाप्त होकर अराजकता का शासन स्थापित हो जाएगा। न्यायपालिका की आलोचना और न्यायपालिका का अपमान, दोनों अलग बातें हैं। लोकतंत्र पहले की अनुमति देता है, दूसरे की नहीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज का समाज पहले की तुलना में कहीं अधिक अधीर हो गया है। डिजिटल युग में लगभग हर सेवा कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो जाती है। मोबाइल पर भोजन मंगाया जा सकता है, बैंकिंग हो सकती है, टिकट बुक हो सकता है और जानकारी तुरंत मिल जाती है। इसी मानसिकता का प्रभाव न्याय के प्रति अपेक्षाओं पर भी पड़ा है। लोग चाहते हैं कि अदालतें भी तुरंत फैसला सुनाएं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया किसी तकनीकी सेवा की तरह नहीं चल सकती। प्रत्येक मामले में तथ्य, साक्ष्य, गवाह, कानून और दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तार से परीक्षण आवश्यक होता है। यदि केवल तेजी के लिए न्यायिक प्रक्रिया को छोटा कर दिया जाए, तो निर्दोष भी दंडित हो सकते हैं और दोषी भी बच सकते हैं। इसलिए त्वरित न्याय आवश्यक है, लेकिन जल्दबाजी में दिया गया न्याय नहीं। यही कारण है कि न्यायिक सुधार की चर्चा केवल मामलों के निपटारे की गति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। न्यायालयों की संख्या बढ़ाना, न्यायाधीशों के रिक्त पद शीघ्र भरना, आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाना, डिजिटल सुनवाई की व्यवस्था मजबूत करना, अनावश्यक स्थगनों पर नियंत्रण और वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणालियों को प्रोत्साहन देना भी उतना ही आवश्यक है। यदि इन क्षेत्रों में सुधार होगा, तो लंबित मामलों की संख्या कम होगी और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि क्या संस्थाओं का सम्मान केवल संवैधानिक पद के कारण बना रहता है या उसके पीछे कार्यक्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः दोनों बातें समान रूप से आवश्यक हैं। संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र और सम्मानित स्थान देता है। इस सम्मान की रक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। साथ ही न्यायपालिका पर यह उत्तरदायित्व भी है कि वह समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी न्याय प्रदान करे। जनता का विश्वास केवल संवैधानिक व्यवस्था से नहीं, बल्कि उसके अनुभवों से भी निर्मित होता है।

इतिहास बताता है कि जब भी किसी संस्था और समाज के बीच संवाद कमजोर होता है, तब टकराव की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस घटना को केवल अनुशासनहीनता मानकर भुला देना भी उचित नहीं होगा। यह समझना होगा कि आखिर ऐसे व्यवहार की पृष्ठभूमि क्या है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में मानसिक तनाव, निराशा या न्यायिक प्रक्रिया से उपजे असंतोष के कारण ऐसा करता है, तो यह भी चिंता का विषय है। यदि ऐसा केवल सस्ती लोकप्रियता या प्रचार पाने के लिए किया गया, तब भी यह समाज में बढ़ती सनसनी प्रियता का संकेत है। दोनों ही स्थितियों में समाधान केवल दंड नहीं, बल्कि संस्थागत आत्ममंथन भी है। सोशल मीडिया ने भी इस प्रकार की घटनाओं को नया आयाम दिया है। पहले अदालतों में होने वाली घटनाएं सीमित दायरे में रहती थीं। अब कुछ ही मिनटों में उनका वीडियो और विवरण लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। इससे कई बार तथ्य पीछे छूट जाते हैं और भावनाएं आगे निकल जाती हैं। लोग बिना पूरी जानकारी के पक्ष और विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। न्यायपालिका जैसी गंभीर संस्था के संदर्भ में यह प्रवृत्ति और भी चिंताजनक है क्योंकि इससे जनविश्वास प्रभावित हो सकता है।

यह भी याद रखना चाहिए कि न्यायपालिका की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों पर समय-समय पर विद्वानों, वकीलों, पत्रकारों और नागरिकों ने असहमति जताई है। लेकिन यह असहमति हमेशा तर्क, कानून और संवैधानिक भाषा के माध्यम से व्यक्त की गई। यही लोकतांत्रिक संस्कृति है। व्यक्तिगत अपमान, अभद्रता और संस्थागत अवमानना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करते हैं। दूसरी ओर न्यायपालिका को भी यह समझना होगा कि सम्मान केवल अपेक्षा करने से नहीं मिलता, बल्कि निरंतर अर्जित भी करना पड़ता है। जब लोगों को समय पर न्याय मिलता है, फैसले स्पष्ट और तार्किक होते हैं, प्रक्रियाएं पारदर्शी होती हैं और अदालतें आम नागरिक के लिए सुलभ बनती हैं, तब सम्मान स्वतः बढ़ता है। इसलिए न्यायिक सुधार केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास की भी आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय में घटी यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल अदालत के भीतर की घटना नहीं है। यह समाज के भीतर बढ़ती अधीरता, संस्थाओं के प्रति बदलते दृष्टिकोण, सोशल मीडिया के प्रभाव और न्याय व्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों का संयुक्त प्रतिबिंब है। इस घटना की निंदा करना आवश्यक है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही इस घटना को एक चेतावनी के रूप में भी देखना चाहिए कि यदि न्यायिक व्यवस्था को अधिक सक्षम, तेज और नागरिक केंद्रित नहीं बनाया गया, तो जनता और संस्थाओं के बीच विश्वास का अंतर और बढ़ सकता है। लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान की पुस्तकों में नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास में निहित होती है। न्यायपालिका उस विश्वास की अंतिम संरक्षक है। इसलिए एक ओर नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अदालतों की गरिमा और संवैधानिक मयार्दा का सम्मान करें, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका का दायित्व है कि वह समयबद्ध, सुलभ और प्रभावी न्याय देकर उस सम्मान को और अधिक मजबूत बनाए। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है।

पुरस्कारों का अर्थशास्त्र

-प्रियंका सौरभ

साहित्य का मूल उद्देश्य समाज को संवेदनशील बनाना, विचारों को दिशा देना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करना है। एक सच्चा साहित्यकार पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के अंतःकरण को झकझोरने के लिए लिखता है। फिर भी यह भी उतना ही सत्य है कि उत्कृष्ट रचनाकारों को सम्मानित करना किसी भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी है। पुरस्कार न केवल लेखक की साधना को सार्वजनिक स्वीकृति देते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। किंतु जब पुरस्कार सम्मान का माध्यम न रहकर आय का साधन, प्रचार का उपकरण और व्यक्तिगत लाभ का व्यवसाय बन जाएँ, तब साहित्य की आत्मा आहत होती है। आज साहित्यिक जगत में ऐसे अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, जो पुरस्कारों के अर्थशास्त्र और उनकी पारदर्शिता पर गंभीर विमर्श की माँग करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में साहित्यिक पुरस्कारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। छोटे-बड़े शहरों में अनेक संस्थाएँ विभिन्न विधाओं में पुरस्कार घोषित कर रही हैं। पहली दृष्टि में यह साहित्य के लिए शुभ संकेत प्रतीत होता है, क्योंकि इससे लेखकों को मंच और पहचान मिलती है। किंतु जब इन पुरस्कारों के पीछे की आर्थिक संरचना को देखा जाता है तो कई बार तस्वीर चिंताजनक दिखाई देती है। प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सदस्यता शुल्क, अनिवार्य पुस्तकें, स्मारिका सहयोग, समारोह शुल्क और अन्य मदों के माध्यम से बड़ी राशि एकत्र की जाती है, जबकि वास्तविक पुरस्कार राशि अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इससे यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या पुरस्कार साहित्यकारों के सम्मान के लिए हैं या संस्थाओं की आय बढ़ाने का माध्यम?

कुछ संस्थाएँ पुरस्कारों के लिए ऐसी शर्तें रखती हैं कि केवल प्रकाशित पुस्तक वाले लेखक ही आवेदन कर सकें। इसके साथ ही पुस्तक की दो या तीन प्रतियाँ भेजना अनिवार्य होता है। आवेदन शुल्क अलग से लिया जाता है। यदि सैकड़ों लेखक आवेदन करते हैं तो संस्था के पास लाखों रुपये एकत्र हो जाते हैं। पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है और अधिकांश प्रतिभागियों को केवल धन्यवाद या सहभागिता प्रमाणपत्र मिलता है। आर्थिक दृष्टि से यह मॉडल संस्थाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होता है, जबकि लेखक अपनी रचना, पुस्तक, डाक व्यय और आवेदन शुल्क सहित पर्याप्त धन खर्च कर देता है। यहाँ समस्या केवल शुल्क लेने की नहीं है। यदि कोई संस्था पारदर्शी ढंग से बताती है कि आवेदन शुल्क मूल्यांकन, डाक, निर्णायकों के मानदेय, सभागार, स्मारिका और प्रशासनिक खर्चों के लिए आवश्यक है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आय और व्यय का कोई सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं होता। लेखकों को यह तक ज्ञात नहीं होता कि निर्णायक कौन हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है और चयन के मानदंड क्या हैं। पारदर्शिता के अभाव में संदेह जन्म लेता है और सम्मान की गरिमा कम होने लगती है।

आज साहित्य में एक नई प्रवृत्ति यह भी देखने को मिल रही है कि पुरस्कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, किंतु उनकी विश्वसनीयता घटती जा रही है। अनेक पुरस्कार ऐसे हैं जिनका साहित्यिक योगदान से अधिक संबंध प्रचार-प्रसार से दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े पोस्टर, भव्य मंच, आकर्षक बैनर और लंबी सम्मान सूची देखने को मिलती है, लेकिन साहित्यिक गुणवत्ता पर गंभीर चर्चा कम दिखाई देती है। सम्मान समारोह कभी-कभी साहित्यिक आयोजन कम और प्रचार कार्यक्रम अधिक लगने लगते हैं।

इस प्रवृत्ति का सबसे अधिक नुकसान नवोदित लेखकों को होता है। वे सम्मान प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा में आवेदन शुल्क जमा करते हैं, पुस्तकें भेजते हैं और पुरस्कार की आशा करते हैं। कई बार उन्हें केवल सहभागिता प्रमाणपत्र या मंच पर एक तस्वीर मिलती है। धीरे-धीरे यह धारणा बनती है कि साहित्य में भी सफलता का रास्ता गुणवत्ता से अधिक आर्थिक योगदान और संपर्कों से होकर गुजरता है। यह धारणा साहित्य के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है।

पुरस्कारों की विश्वसनीयता का दूसरा आधार निर्णायक मंडल होता है। यदि निर्णायक स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिष्ठित हों तथा उनकी चयन प्रक्रिया सार्वजनिक हो, तो पुरस्कार की प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ जाती है। किंतु यदि निर्णायकों के नाम गोपनीय रखे जाएँ, चयन के कारण न बताए जाएँ और परिणाम केवल औपचारिक घोषणा बनकर रह जाएँ, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। साहित्य में विश्वास ही सबसे बड़ी पूँजी है, और पारदर्शिता उसके संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह भी सच है कि सभी साहित्यिक संस्थाओं को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। देश में अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएँ और अकादमियाँ वर्षों से निष्पक्ष और सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। वहाँ आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता या यदि लिया जाता है तो उसका स्पष्ट औचित्य और लेखा-जोखा उपलब्ध रहता है। चयन प्रक्रिया बहुस्तरीय होती है और निर्णायक मंडल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ऐसे पुरस्कार साहित्यकारों के लिए प्रेरणा बनते हैं और समाज में साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। दूसरी ओर कुछ संस्थाएँ पुरस्कारों को नियमित आय के स्रोत के रूप में विकसित करती दिखाई देती हैं। यदि किसी प्रतियोगिता में पाँच सौ या एक हजार आवेदन आते हैं और प्रत्येक से शुल्क लिया जाता है, तो संस्था के पास बड़ी राशि एकत्र हो जाती है। यदि उसी राशि का बहुत छोटा भाग पुरस्कारों और आयोजन पर खर्च हो तथा शेष राशि के उपयोग का कोई सार्वजनिक विवरण न हो, तो आलोचना होना स्वाभाविक है। साहित्यिक संस्थाएँ सामाजिक विश्वास पर चलती हैं; इसलिए उन्हें आर्थिक पारदर्शिता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पुरस्कारों के अर्थशास्त्र का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। सम्मान पाने की इच्छा प्रत्येक रचनाकार में होती है। यह स्वाभाविक भी है। किंतु इसी इच्छा का यदि व्यावसायिक दोहन होने लगे तो यह साहित्यिक नैतिकता के विरुद्ध है। सम्मान कभी खरीदा नहीं जा सकता और न ही आवेदन शुल्क के अनुपात में उसका मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। वास्तविक पुरस्कार वह है जिसे समाज और समय स्वीकार करे। समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले प्रत्येक साहित्यिक संस्था को अपनी आय और व्यय का वार्षिक विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। आवेदन शुल्क का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, निर्णायक मंडल, मूल्यांकन के मानदंड और परिणामों की संक्षिप्त रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि पुरस्कार वास्तव में साहित्य सेवा के लिए हैं तो संस्था को यह भी बताना चाहिए कि प्राप्त राशि का कितना भाग साहित्यिक गतिविधियों, पुस्तकालयों, युवा लेखकों, शोध और प्रकाशन पर व्यय किया गया।

इसके अतिरिक्त पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। कम पुरस्कार, लेकिन निष्पक्ष चयन और सम्मानजनक राशि, साहित्यकारों के लिए अधिक प्रेरणादायक होगी। पुरस्कार समारोह की भव्यता से अधिक महत्त्व चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता का होना चाहिए।

करणी सेना के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता बने एड. जितेंद्र शुक्ला

मुंबई (उत्तरशक्ति)। हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदू संगठन करणी सेना ने तेजतर्रार युवा अधिवक्ता एडवोकेट जितेंद्र रमाशंकर शुक्ला को महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। करणी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष देवीचंद सिंह बारवाल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि एड. शुक्ल द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों और निर्भीकता के साथ हमेशा राष्ट्रीय विचारधारा का साथ देने की भावना को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में परिवहन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे एड. जितेंद्र शुक्ला उच्च शिक्षित होने के साथ-साथ पूरे निर्भीकता के साथ अपनी बात रखते हैं। उन्हें करणी सेना का महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने स्वागत किया है।

नाबार्ड और एनएसडीसी ने ग्रामीण उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए 'ग्रामोदयम' कार्यक्रम शुरू किया

मुंबई। ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना हमेशा से नाबार्ड के विजन और विकासात्मक दायित्व का मूल आधार रहा है। नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण भारत की उद्यमशील क्षमता को नई दिशा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए परिवर्तनकारी उद्यमिता विकास कार्यक्रम ग्रामोदयम का शुभारंभ नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. शाजी के. वी. ने किया।

यह पहल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से लागू की जा रही है। यह ग्रामीण उद्यमिता के लिए एक सशक्त और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (आईआईडी) के माध्यम से किया जाएगा।

ग्रामोदयम ग्रामीण भारत के युवाओं को समर्पित एक विशेष पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आकांक्षी उद्यमियों की पहचान करना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। इसके तहत उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल, उद्यमिता संबंधी दक्षताएं और आवश्यक सहयोग तंत्र तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। युवा नवाचारकताओं को उनके विचारों को व्यवहार्य उद्यमों में परिवर्तित करने में सक्षम बनाकर ग्रामोदयम का लक्ष्य स्थानीय अवसरों को सतत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के सशक्त माध्यमों में बदलना है। यह कार्यक्रम डिजिटल-प्रथम (डिजिटल-फर्स्ट) हाइब्रिड कार्यान्वयन मॉडल पर आधारित है, ताकि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक समान रूप से इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया सहभागिता, सामुदायिक संपर्क तथा जमीनी स्तर पर जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें उद्यमिता की एक सुव्यवस्थित यात्रा के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना से 81 लाख महिलाएं बाहर, ई-केवाईसी सत्यापन के बाद सरकार की बड़ी कार्रवाई

मुंबई। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने जानकारी दी है कि कई महीनों तक चली ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना से करीब 81 लाख पंजीकृत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। मंत्री ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट किया कि अपात्र लाभार्थियों, आयकर दाताओं और सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को व्यवस्थित तरीके से हटाने के लिए यह सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य थी।अदिति तटकरे ने योजना के आंकड़ों का विवरण देते हुए बताया कि शुरूआत में 2.63 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 2.47 करोड़ महिलाएं लाभार्थी बनीं और उन्हें मासिक आर्थिक सहायता दी गई। हालांकि, जब विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया शुरू की, तो यह संख्या कम होने लगी। उन्होंने बताया कि लगभग 62 लाख महिलाओं ने समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके कारण उन्हें योजना से बाहर करना पड़ा। मंत्री ने आगे बताया कि करीब 16 लाख लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक पाई गई, जबकि 4.42 लाख महिलाओं को इसलिए अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी था। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ पुरुषों और स्वयं सरकारी कर्मचारियों ने भी इस योजना के लिए पंजीकरण कराया था और इसका लाभ उठाया था। सरकार ने अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया है और यह राशि सरकारी खजाने में जमा की जा रही है। इस बीच, विपक्षी दलों ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस योजना के लिए स्वीकृत बजट से 3,541 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए हैं और इस अतिरिक्त व्यय का कोई हिसाब नहीं रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आवास और स्वच्छता जैसी बुनियादी योजनाओं के बजट में कटौती करके इस योजना पर भारी खर्च किया गया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले वोट पाने के लिए नियमों की अनदेखी कर महिलाओं को लाभ दिया गया और अब चुनाव के बाद उन्हें अपात्र बताकर हटाया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता अनिल शिदोरे ने भी इस घटनाक्रम को परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि अपात्र लाभार्थियों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करना सरकारी धन का दुरुपयोग है।

नथिंग फोन 4b की बिक्री शुरू

मुंबई/पटना। लंदन स्थित कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड नथिंग ने अपने नए (b) सीरीज के पहले स्मार्टफोन फोन (4b) की बिक्री शुरू होने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि नथिंग इकोसिस्टम का अनुभव लेने का यह सबसे किफायती तरीका है। 8जीबी + 128जीबी वेरिएंट की प्रभावी शुरूआती कीमत 29,999 रुपये और 8जीबी + 256जीबी वेरिएंट की 33,699 रुपये रखी गई है। इन कीमतों में 7.5 प्रतिशत इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस शामिल हैं। फोन (4b) की बिक्री 14 जुलाई, 2026 से फ्लिपकार्ट और प्रमुख रिटेल पार्टनर्स जैसे क्रोमा, रिलायंस डिजिटल और विजय सेल्स के स्टोर्स पर शुरू होगी। फोन (4a) सीरीज की कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए फोन (4b) में नथिंग का सिग्नेचर पारदर्शी डिजाइन और ग्लिफ इंटरफेस दिया गया है। इसके साथ दमदार स्नैपड्रैगन परफॉर्मेंस, हर तरह की जरूरतों के लिए मुफीद कैमरा सिस्टम शानदार एमोलेड डिस्प्ले और एसेंशियल एआई टूल्स के साथ पूरा नथिंग ओएस एक्सपीरियंस मिलता है। नथिंग इकोसिस्टम में कदम रखने वाले यूजर्स के लिए फोन (4b) को एक बेहतरीन शुरूआती डिवाइस के तौर पर तैयार किया गया है।

शिवसेना शिंदे गुट के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष शिबू आर. शेख समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल

चेतन निर्मल
डोंबिवली (उत्तरशक्ति)। शिवसेना (शिंदे गुट) के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष शिबू आर. शेख ने अपने समर्थकों और कार्यकताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया। यह पक्ष प्रवेश कार्यक्रम डोंबिवली शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अमित भास्कर म्हात्रे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अमित भास्कर म्हात्रे ने शिबू आर. शेख एवं उनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए सभी कार्यकताओं का पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं

देते हुए कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। शिबू आर. शेख के साथ इरफान सैयद, जोहेब सैयद, अब्दुल कादर, रहमान चौधरी, अहमद रजा शेख, रेहान शेख, मीना शेख, उदा शेख, इमरान शेख, निसार सैयद, रजी अंबितकर, अयान शेख, शबाना शेख, रेश्मा शेख, रेहाना मेनन, ईसा खान, रेहना शेख, शफिका शेख, अफिया शेख, समीर शेख, साहिल शेख तथा साहेबान शेख ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने सभी नए सदस्यों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर अमित भास्कर म्हात्रे ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सामूहिक पक्ष प्रवेश से डोंबिवली शहर में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा पार्टी का जनाधार बढ़ेगा।

हिमालय पर्वतीय संघ के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर बच्चों को मिला शिक्षा एवं स्वच्छता का उपहार

मुंबई (उत्तरशक्ति)। हिमालय पर्वतीय संघ घाटकोपर के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर उनके द्वारा संचालित भारतरत्न गोविंद वल्लभ पंत हाई स्कूल के विद्यार्थियों के बीच *निःशुल्क नोटबुक एवं स्वच्छता किट वितरित किया गया। इस सुनहरे मौके पर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और उनके उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद थी । यह संस्थान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था ।संस्था को विश्वास है कि हिमालय पर्वतीय संघ शिक्षा और स्वच्छता, दोनों को साथ लेकर एक सशक्त और जागरूक समाज की नींव रखेंगे। इस सेवा कार्य में सहयोग देने वाले सभी स्वयंसेवकों एवं पहाड़ी प्रवाशी सोसायटी के सभी कर्मठ कार्यकताओं तथा हिमालय पर्वतीय संघ ने हृदय से आभार व्यक्त किया। हिमालय पर्वतीय संघने सभी समाजिक संस्थाओं आग्रह किया कि मिलकर शिक्षा, स्वच्छता और मानव सेवा की इस यात्रा को आगे बढ़ाएँ।

योगेश जगदाले भाजपा जिला उपाध्यक्ष नियुक्त

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मीरा भायंदर के विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष दिलीप जैन द्वारा योग्य,कर्मठ व अनुभवी अधिवक्ता योगेश जगदाले को कानूनी सलाहकार विभाग में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है ।

इस अवसर पर मुख्य रूप से अधिवक्ता बी के सिंह,डॉक्टर सुरेश येवले परिवहन समिति के सभापति अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा व कार्यालय प्रमुख अण्णा आसीनकर उपस्थित थे। अपनी नियुक्ति पर जगदाले ने विधायक मेहता, जिला अध्यक्ष जैन और पूरे भाजपा संगठन के प्रति आभार जताया है। और कहा है कि पार्टी ने हमारे ऊपर जो भरोसा दिखाया है उसे मैं पूरी निष्ठा,लगन व पूरी ईमानदारी के साथ सदैव निर्वाह करता रहूंगा। और पार्टी के उत्थान के प्रति हमेशा समर्पित रहूंगा। जिला भाजपा कानूनी विभाग में उपाध्यक्ष बनाये जाने पर सैकड़ो लोगों ने अधिवक्ता योगेश जगदाले को अपनी शुभकामनाएं दी है।

कल्याण में आगरी-कोली समाज भवन के लिए भूमिपुत्रों की एकजुटता, समाज भवन का किया भूमिपूजन

कल्याण (उत्तरशक्ति)। आगरी-कोली समाज भवन की मांग को लेकर कल्याण के मलंगगढ़ रोड स्थित नांदीवली में स्थानीय भूमिपुत्र और आगरी-कोली समाज के लोग एकजुट हुए। विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में प्रस्तावित आगरी-कोली समाज भवन का भूमिपूजन किया गया।

समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्षों से शासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष समाज भवन के लिए लगातार मांग और पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। उनका कहना है कि शहर के विकास कार्यों के लिए

उनकी जमीनें अधिग्रहित की गईं, जबकि अन्य समाजों को समाज भवन और सामुदायिक हॉल के लिए जगह उपलब्ध कराई गई। ऐसे में आगरी-कोली समाज के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यह सवाल भी उन्होंने उठाया। समाज के लोगों ने कहा कि नांदीवली क्षेत्र में आगरी-कोली समाज भवन का निर्माण उनकी वर्षों पुरानी मांग है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण सभी राजनीतिक दलों से जुड़े आगरी-कोली समाज के लोग एक मंच पर आए और नांदीवली तालाब के समीप प्रस्तावित स्थान पर समाज भवन का भूमिपूजन कर अपने अधिकार की मांग को बुलंद किया। इस अवसर गणेश ढोणे, रामदास ढोणे, प्रल्हाद ढोणे, बापू ढोणे सहित समाज के वरिष्ठ नागरिक, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय आगरी-कोली समाज के लोग मौजूद रहे। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समाज भवन के निर्माण के लिए शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आगे व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

अरविंद सावंत का आरोप: महाराष्ट्र की 'माझी लड़की बहिन' योजना से 90 लाख नाम कटे

मुंबई। शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने 'माझी लड़की बहिन योजना' से 90 लाख लाभार्थियों को कथित तौर पर हटाने के कदम को संविधान का घोर उल्लंघन बताया और सरकारी फंड के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। पत्रकारों से बात करते हुए सावंत ने कहा कि जिन महिलाओं के नाम इस स्कीम से हटाए गए, उनमें से कई ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी गठबंधन का समर्थन किया था। सावंत ने कहा कि इस स्कीम से लाखों महिलाओं के नाम हटा दिए गए। ये वही महिलाएं थीं जो इस लालच में आकर मौजूदा सरकार को सत्ता में ले आईं; और

सिर्फ. महिलाओं ने ही वोट नहीं दिया, बल्कि उनके परिवारों ने भी वोट दिया। अब सरकार क्या करने जा रही है? उन्होंने नाम हटा दिए हैं। नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यह जनता का पैसा है। सावंत ने आगे कहा कि यह हटाना संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि यह संविधान का गंभीर उल्लंघन है, और इसीलिए मैं इस सरकार के कामों पर गंभीर सवाल उठाना चाहता हूँ। हालाँकि विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, फिर भी उअऋकी रिपोर्ट कई मुद्दों की ओर इशारा करती है। कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है; यह राज्य के राजस्व के 100 प्रतिशत से भी ज्यादा होने वाला है। उन्होंने हमारी राज्य सरकार के लिए ऐसी ही गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग और महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई 'माझी लड़की बहिन योजना' राज्य भर की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को सीधे उनके खाते में 1,500 रुपये दिए जाते हैं।

उद्धव ठाकरे का राहुल गांधी को दो टूक, बोले- कॉकरोच पार्टी के समर्थन में जंतर मंतर आएं

मुंबई। शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और अपना समर्थन देने की अपील की। ठाकरे ने इस संगठन और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रति अपना समर्थन जताया और विरोध प्रदर्शन के लिए और अधिक समर्थन की मांग की। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में UBT प्रमुख ने कहा कि वह विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर जाएंगे और उन्होंने राहुल गांधी से भी वहां जाने की अपील की। ठाकरे ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए। जिन लोगों को देश के युवाओं

पर भरोसा है, उन्हें भी जाना चाहिए। पूरे देश के लोगों को सड़कों पर उतरकर उनका समर्थन करना चाहिए। ठाकरे 20 जुलाई को दिल्ली जाकर जंतर-मंतर का दौरा करेंगे और चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ मिलकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने 20 जून को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया है। बोस्टन से लौटे अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाले इस संगठन ने ठएएळ-वऋपेपर लीक जैसी परीक्षाओं में कई गड़बड़ियों के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।

समाजसेवी परशुराम पाल ने पत्रकारों को रैनकोट देकर किया सम्मान, लेखन सामग्री का किया वितरण

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। मानसून के दौरान पत्रकारों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए पूजा टीवी 24 यूट्यूब चैनल के संपादक एवं समाजसेवी परशुराम पाल ने पत्रकार सम्मान की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए रविवार को बंजारपट्टी नाका स्थित श्री देवी ज्वेलर्स के सामने कौमी एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष तूफैल फारूकी के कार्यालय में 55 पत्रकारों को रेनकोट एवं लेखन सामग्री वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौमी एकता फाउंडेशन के भिवंडी अध्यक्ष तूफैल फारूकी तथा हिंदी-उर्दू पत्रकार संघ के अध्यक्ष अब्दुल गनी खान उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार आचार्य सूरजपाल यादव एवं खान फखरे आलम सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ परशुराम पाल की सुपुत्री पूजा पाल ने अतिथियों का शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत कर किया। इसके पश्चात अतिथियों ने

भी पूजा पाल एवं परशुराम पाल का शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया तथा पत्रकार हित में किए जा रहे इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। अतिथियों एवं परशुराम पाल के हाथों सभी उपस्थित 55 पत्रकारों को रेनकोट, लेखन सामग्री तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि बारिश के मौसम में पत्रकारों को विषम परिस्थितियों में भी समाचार संकलन के लिए लगातार मैदान में रहना पड़ता है। ऐसे समय में समाजसेवी परशुराम पाल द्वारा पत्रकारों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना न केवल उनकी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का परिचायक है, बल्कि पत्रकार समाज के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। सभी वक्ताओं ने इस पहल की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए परशुराम पाल का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें शहर के विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।

पान हेल्थ ने बेबी केयर, महिला हाइजीन और एडल्ट केयर में बढ़ाया विस्तार

मुंबई (उत्तरशक्ति)। हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाने वाली भारत की प्रमुख कंपनियों में शामिल पान हेल्थ बड़े स्तर पर उत्पादन, लगातार नए प्रोडक्ट्स और भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ बेबी केयर, महिला हाइजीन और एडल्ट केयर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। पान हेल्थ अपने प्रमुख ब्रांड लिटिल एंजेल (बेबी केयर), एवरटीन (महिला हाइजीन) और लिबर्टी (एडल्ट केयर) के जरिए हर उम्र के लोगों के लिए हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाती है। स्वास्थ्य, हाइजीन और वेलनेस के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता को देखते हुए कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स ला रही है और अपने प्रोडक्ट्स का दायरा बढ़ा रही है। लिटिल एंजेल के तहत कंपनी अब डायपर और वाइप्स के अलावा प्रीमियम बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी पेश कर रही है। इनमें बेबी फीडिंग और बाथ केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स, प्रीमियम सिंडेट बार, प्रीमियम बेबी सोप और अन्य जरूरी बेबी केयर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वहीं एवरटीन ब्रांड के तहत प्रीमियम सैनिटरी पैड, प्रीमियम पीरियड पैंटी, पैंटी लाइनर और महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई नए हाइजीन प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं।

इन सभी पहलों का उद्देश्य ग्राहकों की बदलती जरूरतों के मुताबिक बेहतर और नए प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना है।

पान हेल्थ की विकास यात्रा की सबसे बड़ी ताकत गुजरात के राजकोट में स्थित भारत की सबसे बड़ी डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वर्ष 2017 में शुरू हुई यह आधुनिक उत्पादन सुविधा 30 एकड़ में फैली हुई है और इसमें 7 लाख वर्ग फुट से अधिक का उत्पादन क्षेत्र है। यहां हर साल 3.7 अरब से ज्यादा हाइजीन प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड मशीनें, सख्त क्वालिटी जांच और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों की मदद से कंपनी बड़े स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाले हाइजीन प्रोडक्ट्स तैयार करती है। इस अवसर पर पान हेल्थ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उएड) एवं प्रबंध निदेशक चिराग पान ने कहा, पान हेल्थ में हमारा मानना है कि अच्छी हाइजीन से बेहतर और स्वस्थ जीवन की शुरूआत होती है। हमारा लक्ष्य भारत में ही अच्छी गुणवत्ता वाले, किफायती और भरोसेमंद हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाना है। भारत की सबसे बड़ी डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ हम लगातार नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं और बेबी केयर, महिला हाइजीन तथा एडल्ट केयर में अपने प्रोडक्ट्स का दायरा बढ़ा रहे हैं। 'मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड' की सोच के साथ हम न सिर्फ भारत के लोगों के लिए बेहतर हाइजीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बल्कि भारत को इस क्षेत्र में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं।

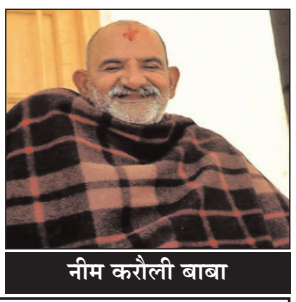

नीम करौली बाबा

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय:
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

धार्मिक टिप्पणी पर कांग्रेस का विरोध, डीएम को सौंपा ज्ञापन

◆ सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की उठी मांग

प्रियेश गुप्ता रुद्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सोशल मीडिया पर कथित धार्मिक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह एवं शहर अध्यक्ष आरिफ खान के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि एक सोशल मीडिया अकाउंट से विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक व्यक्तित्वों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं। हालिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की।

ज्ञापन के बाद डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी धर्म, धर्मगुरु या धार्मिक आस्था का अपमान स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई आवश्यक है, ताकि समाज में सौहार्द और शांति बनी रहे।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

इस दौरान डॉ. परमेंदर सिंह, जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह 'डब्बू', पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय माली, सभासद शहनवाज मंजूर, अबुजर शेख, जिला सचिव इरशाद खान, मोहम्मद ताहिर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

देवांश प्रथम, अनुराग यादव द्वितीय, अभिनव तृतीय स्थान पर पीयू में निबंध लेखन प्रतियोगिता संपन्न

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेर्शों के क्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह-2026 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर स्थित रज्जू भैया संस्थान में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुलपति प्रो. वंदना सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय परिसर के साथ-साथ जनपद जौनपुर एवं गाजीपुर के सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्धारित विषयों के अनुसार प्रतियोगिता चार विषयों– भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बना, राज्य सरकार के दो अच्छे कार्य, भारत सरकार के दो अच्छे कार्य तथा पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय/संस्थान में चिकित्सा, कृषि, शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्य– पर आयोजित की गई।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देवांश श्रीवास्तव (तिलकधारी सिंह महाविद्यालय, जौनपुर) ने प्रथम, अनुराग यादव (विश्वविद्यालय परिसर) ने द्वितीय तथा अभिनव यादव (मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज, जौनपुर) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव के निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के सफल संचालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों प्रभात तिवारी, हर्ष यादव एवं अर्पिता यादव ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर प्रो. मिथिलेश सिंह, प्रो. प्रमोद कुमार यादव, डॉ. अनुराग मिश्र, डॉ. प्रियंका कुमारी, डॉ. मिथलेश यादव, डॉ. सुजीत चौरसिया, डॉ. नितेश जायसवाल, डॉ. अजीत सिंह, प्रो. प्रमोद कुमार, डॉ. वनिता सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बननें तक रखे सुरक्षित: पूर्व विधायक दिनेश चौधरी

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। एक पेड़ माँ के नाम थीम के तहत धरौरा गांव मे आयोजित कार्यक्रम मे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केराकत के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने पौधरोपण कर हरियाली का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाये। पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि माँ के सम्मान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप सभी लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की ! उन्होनें कहा कि प पेड़ न केवल शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जैव विविधता को सुरक्षितरखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण अभियान में केराकत तहसील के उप जिलाधिकारी सुनील कुमार और तहसीलदार अजीत कुमार भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए सभी लोगों ने पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने और लगाए गए पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया ! कार्यक्रम के अंत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक केराकत ने लोगों से कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और सुरक्षा भी जरूरी है यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखें तो आने वाली पीढियों को स्वच्छ सुरक्षित और हरित वातावरण की अमूल सौगात मिल सकती है।

नशे में डांस करना पड़ा भारी, तीसरी मंजिल से गिरकर व्यक्ति की दर्दनाक मौत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्धीकपुर स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के उर्दू बाजार निवासी अशोक कुमार गौतम अपने एक रिश्तेदार के यहां कांशीराम आवास कॉलोनी आए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, उन्होंने शराब का सेवन किया था और नशे की हालत में तीसरी मंजिल पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े। हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल करंजाकला ब्लॉक स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सरायख्वाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। घटना के बाद कॉलोनी में शोक के साथ-साथ विभिन्न तरह की चचाएँ भी हो रही हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है।

दुद्धी के एसडीएम निखिल यादव का भदोही तबादला, सोनभद्र को मिले तीन नए उप जिलाधिकारी

सुशील कुमार तिवारी

दुद्धी, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ट्रांसफर नीति के तहत प्रदेश के 182 पीसीएस अधिकारियों (उप जिलाधिकारियों) के तबादले किए गए हैं। इसी क्रम में जनपद सोनभद्र की दुद्धी तहसील में लंबे समय से तैनात उप जिलाधिकारी निखिल यादव का तबादला भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कर दिया गया है। वहीं शासन ने जनपद सोनभद्र के लिए वर्ष 2020 बैच के तीन पीसीएस अधिकारियों रवि कुमार, आकांक्षा गौतम एवं विशाल कुमार की तैनाती की है। हालांकि इन तीनों अधिकारियों को जिले की किस तहसील अथवा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसका निर्णय प्रशासन द्वारा जल्द किया जाएगा। एसडीएम निखिल यादव के तबादले की सूचना मिलते ही दुद्धी क्षेत्र में चचाओं का दौर शुरू हो गया। उनके कार्यकाल को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ लोग उनके स्थानांतरण पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं कुछ किसानों और स्थानीय लोगों ने इसे सकारात्मक बदलाव बताते हुए खुशी जाहिर की है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिले में आए नए उप जिलाधिकारियों को किस स्थान पर तैनाती मिलती है और दुद्धी तहसील की कमान किस अधिकारी को सौंपी जाती है।

जिला सेवायोजन कार्यालय, कैम्पस में 15 जुलाई 2026 को रोजगार मेला का आयोजन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। निदेशक, सेवायोजन उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला सेवायोजन कार्यालय परिसर निकट नारायण नर्सिंग होम जौनपुर में 15 जुलाई 2026 को प्रातः 10:00 बजे से रोजगार मेला का आयोजन किया जाना हैं। जिसमें निजी क्षेत्र की कम्पनियों ब्लिंकिट, इंडिया थर्मिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेलस्पन लिविंग लिमिटेड, मेसर्स अन्नपूर्णा रिक्रूटमेंट रिसर्च सेंटर, केयर हेल्थ नर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिभाग किया जाना प्रस्तावित हैं, शैक्षिक योग्यताः- हाई स्कूल, इंटर, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष के प्रतिभाग कर सकते हैं। जिसमें अभ्यर्थी अपने योग्यतानुसार प्रतिभाग करते हुए विभिन्न पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते है।

जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया की रोजगार मेला में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति आई0डी0 प्रूफ बायोडाटा सहित वेब पोर्टल- rojgarsangam.up.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर लाभान्वित हो सकते है।

यूपी में 182 एसडीएम के बंपर तबादले

जौनपुर के केराकत एसडीएम सुनील कुमार भारती मऊ स्थानांतरित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 182 उपजिलाधिकारियों (एसडीएम)

के तबादले किए हैं। देर रात जारी स्थानांतरण सूची में कई जिलों के एसडीएम का कार्यक्षेत्र बदला गया है। इसी क्रम में जौनपुर के केराकत उपजिलाधिकारी सुनील कुमार भारती का तबादला जनपद मऊ कर दिया गया है। शासन के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानांतरण सूची में कानपुर देहात, गाजीपुर, वाराणसी, मैनपुरी, रायबरेली, उन्नाव, आगरा, बरेली, हाथरस, अमरोहा, देवरिया, कौशाम्बी, आजमगढ़ समेत कई जिलों के एसडीएम शामिल हैं। शासन का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। केराकत में नए उपजिलाधिकारी की तैनाती का आदेश शीघ्र जारी होने की संभावना है।

हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान रैली को किया रवाना

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। विकासखंड बक्सा क्षेत्र में नामांकन अभियान के द्वितीय चरण में बक्शा ब्लॉक की स्कूल चलो अभियान रैली को खंड शिक्षा अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली

का शुभारम्भ शंकरगढ़ न्यायपंचायत के पिएम श्री विद्यालय मयंदीपुर से किया गया, जिसमे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन व माल्यार्पण करके किया गया। रैली में हजारों बच्चों ने गाजे बाजे के साथ मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल चल कर नाम लिखाओ, जैसे नारों के साथ बढ़-चढ़ कर भाग लिया।कार्यक्रम में विद्यालय परिवार और नोडल संकुल डॉ मनीष सिंह सोमवंशी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को अंग वस्त्रम और स्मृति चिह्न देकर सम्मनित किया गया।कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ बक्शा सरोज कुमार सिंह, नोडल संकुल डॉ मनीष सिंह सोमवंशी, एआरपी सुशील यादव, संकुल शिक्षक प्रवीण सिंह, सुबोध श्रीवास्तव, राहुल पाण्डेय के साथ साथ प्रधानाध्यापक राजेश सिंह, डॉ निर्भय सिंह, संजय सिंह, भोलानाथ यादव, दिग्विजय यादव, पुष्पा चौधरी, राजकुमार सिंह, संध्या सिंह, पूर्णिमा सिंह, मंजू वर्मा, रंजना मिश्रा, सर्वेश यादव, सुशील सिंह, मो.जमील अहमद, विवेक यादव, मनोज तिवारी, सुनील यादव, तूफान अली, सोनल सिंह, अंकिता यादव, सावित्री विश्वकर्मा, जया तिवारी, सुनीता यादव, शारदा पाल, अलोक त्रिपाठी, विक्रम सिंह, प्रवीण सिंह, मृदुल दुबे, अवधेश यादव, मनोज कुमार, कमल कुमार, मृदुल सिंह सहित कई अन्य लोग लोगों ने प्रतिभाग किया।

मंडलायुक्त ने की जनसुनवाई, अधिक भीड़ होने पर स्वयं पहुंचे फरियादियों के पास

प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाएः मंडलायुक्त

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में आज आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। अधिक भीड़ होने के बावजूद मंडलायुक्त ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जब भीड़ के कारण सभी फरियादियों का क्रमवार उनके पास पहुंचना कठिन हो गया, तब मंडलायुक्त स्वयं आगे बढ़कर फरियादियों के बीच पहुंचे और उनकी शिकायतें सुनीं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए तथा कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मार्निंग वॉक से लौट रही वृद्धा से दिनदहाड़े चेन लूट, बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद

विरोध पर महिला को धक्का देकर किया घायल, 10 ग्राम सोने की चेन लेकर फरार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शहर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह चेन स्नेचिंग की वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ताड़तला स्थित बजरंग घाट मोहल्ले में मार्निंग वॉक से घर लौट रही एक वृद्धा से बाइक सवार दो बदमाशों ने दिनदहाड़े सोने की चेन लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी

जानकारी के अनुसार बजरंग घाट, ताड़तला निवासी श्रीमती दमयंती देवी (पत्नी हीरालाल वर्मा) सोमवार सुबह करीब 6:05 बजे मार्निंग वॉक कर अपने घर के निकट पहुंची थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे और गले में पहनी करीब 10 ग्राम वजनी सोने की चेन झपट ली। जब वृद्धा ने विरोध करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर घायल हो गईं। इसके बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल वृद्धा की मदद की। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। पीड़िता के पुत्र संदीप कुमार वर्मा ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत और आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुबह के समय भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह की दुस्साहसिक वारदात होना पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। लोगों ने पुलिस से नियमित गश्त बढ़ाने तथा चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रारंभिक जांच में घटना कैमरे में कैद होने की पुष्टि हुई है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

जौनपुर में लोजपा (रामविलास) की चुनावी तैयारी तेज, 'पंडित, पासी, पासवान' के नारे के साथ साधा ब्राह्मण समाज

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित अमरनाथ द्विवेदी बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति साझा की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं लोजपा (रामविलास) के पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के प्रधान महासचिव व प्रवक्ता विकास पांडेय ने पौधरोपण के बाद कहा कि पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा।

राजनीतिक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का तेजी से विस्तार कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव

पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। उन्होंने हाल ही में लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पार्टी को प्रदेश में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। विकास पांडेय ने पार्टी के नए नारे ₹गूंजे धरती आसमान, पंडित, पासी, पासवान₹ का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिल रहा है।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य अमित कुमार दुबे, कृष्णा चंद्र तिवारी, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ममता सिंह, प्रवक्ता सनी कुमार यादव, योगेश वर्मा, विद्यालय के शिक्षक तथा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग, पुस्तैनी रास्ता खुलवाने के लिए डीएम से लगाई गुहार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले के खुन्शापुर गांव निवासी सुशील कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफियाओं ने उनके पुस्तैनी रास्ते को बंद कर दिया है और कई आराजियों पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक माह में कई अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

राजस्व टीम से पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि आराजी संख्या 134 (क), 134, 135, 129 और 160 को लेकर कब्जे का विवाद है। शिकायतकर्ता का कहना है कि निष्पक्ष पैमाइश और सीमांकन होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दबंगों के उत्पीड़न से उनका परिवार ही नहीं बल्कि गांव के करीब एक दर्जन परिवार भी परेशान हैं। सुशील कुमार सिंह ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सक्षम राजस्व टीम गठित कर संबंधित आराजियों की निष्पक्ष पैमाइश कराई जाए, बंद किए गए पुस्तैनी रास्ते को तत्काल खुलवाया जाए तथा अवैध कब्जे की जांच कर दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाए।

नोटः यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर तैयार किया गया है। मामले में प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

हरियाली आंदोलन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे डॉ.बृजेश महादेव

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से हरियाली आंदोलन के संयोजक एवं पर्यावरण प्रेमी शिक्षक डॉ. बृजेश महादेव लगातार जन-जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनके नेतृत्व में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय, पल्हारी (नगवां) में विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। डॉ. महादेव ने बताया कि उनका अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि वनों के संरक्षण, वृक्षों की सुरक्षा तथा वर्षा ऋतु में विभिन्न प्रजातियों के बीजों की बुवाई कर प्राकृतिक वन संपदा का विस्तार करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व लगाए गए अनेक पौधे आज विशाल वृक्ष बन चुके हैं, जो इस अभियान की सफलता का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि 'एक वृक्ष पंद्रह पुत्रों से भी अधिक उपयोगी होता है।' वृक्ष मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन, फल, फूल, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का आधार हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को

अपने जीवन में कम-से-कम एक वृक्ष लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। डॉ. बृजेश महादेव ने बताया कि दार्जिलिंग की प्राकृतिक हरियाली से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पैतृक गाँव भरहरी तथा कर्मभूमि पल्हारी से हरियाली आंदोलन की शुरूआत की थी। आज इस अभियान के माध्यम से हजारों लोगों को पौधे एवं बीज वितरित किए जा चुके हैं तथा उन्हें वृक्षारोपण और पौधों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया है।

उन्होंने बताया कि उनके घर आने वाले प्रत्येक अतिथि को विदाई के समय एक पौधा उपहार स्वरूप दिया जाता है तथा उससे पौधे के संरक्षण का संकल्प भी कराया जाता है। विद्यालय में भी विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण के संस्कार दिए जा रहे हैं, ताकि वे अपने परिवार और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकें। डॉ. महादेव ने लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, उनका संरक्षण करने तथा हरियाली आंदोलन से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहाँ है हरियाली, वहाँ है खुशहाली।

बाइक पिकअप की टक्कर में एक युवक की मौत दूसरे की हालत गंभीर

मुहम्मदाबाद, गाजीपुर(उत्तरशक्ति)। कोतवाली क्षेत्र के बलुआ उर्फ कठउत हरिहरपुर गांव के पास बाइक और पिकअप की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। वही बाइक पर बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया, जिसका डॉक्टरों द्वारा उपचार जारी है। विदित हो कि गौसपुर गांव निवासी लकी गुप्ता एवं सत्यम कनौजिया एक बाइक पर सवार होकर मोहम्मदाबाद की तरफ जा रहे थे कि सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी जिससे लकी गुप्ता की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वही सत्यम कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को देखकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने संबंध में तत्काल पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वाहन को अपने कब्जे में लेकर कोतवाली में खड़ी कर दी। हादसे की सूचना मिलते पूरे गांव गौसपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई वहीं लकी गुप्ता के मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने बताया कि दूसरे युवक

सत्यम कनौजिया की हालत गंभीर है जिसे अस्पताल भिजवा गया तथा उसका इलाज जारी है।

डॉ सुमित ने पदभार संभाला

चिराना। निकटवर्ती तीर्थ स्थल लोहार्गल के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में डॉ सुमित गुर्जर ने चिकित्सा अधिकारी के पद को खास लोगों की मौजूदगी में सोमवार को सम्भाल लिया है। नवलगढ़ क्षेत्र की पुजारी की ढाणी निवासी डॉ सुमित यहां पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय अरवड़ (भीलवाड़ा) से उपनिदेशक कार्यालय भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 2026-27/1483 व राज्यादेश के तहत स्थानांतरण होकर आये है और करीब डेढ़ साल से रिक्त पड़े पर चिकित्सक के पर कार्य ग्रहण किया है।आपको बता देवे कि अब यहां की जनता व दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को नियमित चिकित्सक की सेवाएं सुचारू मिलेगी।

इस दौरान लोहार्गल प्रशासक जगमोहन सिंह शेखावत ने चिकित्सक का स्वागत- सम्मान कर पद आसीन करवाया। इस मौके पर देवकल्प आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर सीकर के डॉ. दिनेश कुमावत,वरिष्ठ कंपाउडर कृष्ण कुमावत, भंवर मंडार,शंकर लाल गुर्जर,बलराम गुर्जर,मोहन गुर्जर,श्यामसुंदर सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे।

चॉइस इंटरनेशनल और एनएच इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के बीच रणनीतिक साझेदारी

मुंबई। भारत के प्रमुख डायवर्सिफाइड वित्तीय सेवा समूहों में से एक चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड ("Choice") ने दक्षिण कोरिया के अग्रणी वित्तीय संस्थानों में से एक एनएच फाइनेंशियल ग्रुप की सब्सिडियरी एनएच इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड ("NHIS") के साथ रणनीतिक गठजोड़ की आज घोषणा की. इसके तहत चॉइस की ब्रोकिंग एवं वेल्थ मैनेजमेंट इकाई चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ("CEBPL") में 900 करोड़ रुपये का रणनीतिक निवेश किया गया.

यह रणनीतिक निवेश चॉइस की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. साथ ही, यह इस बात का भी प्रमाण है कि दक्षिण कोरिया के अग्रणी वित्तीय संस्थानों में शामिल एनएच इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज (NHIS) को भारत में अगली पीढ़ी का वित्तीय सेवा मंच तैयार करने की चॉइस की सोच एवं दीर्घकालिक रणनीति पर पूरा भरोसा है।

भारत का पूंजी बाजार इस समय अभूतपूर्व वृद्धि के दौर से गुजर रहा है। खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी, निवेशकों में बढ़ती जागरूकता तथा डिजिटल तकनीक को तेजी से अपनाए जाने से इस वृद्धि को बल मिला है। ऐसे माहौल में चॉइस को ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, निवेश वितरण तथा पूंजी बाजार से जुड़े अपने कारोबार के विस्तार के साथ-साथ ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के पर्याप्त अवसर दिखाई दे रहे हैं। इस गठजोड़ के तहत एनएचआईएस कंपलसरिली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में 900 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. इस पूंजी का इस्तेमाल ग्रोथ कैपिटल के रूप में किया जाएगा, जिससे कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस का विस्तार करेगी. इसमें एमटीएफ बुक का विस्तार, टेक्नोलॉजी में रणनीतिक निवेश, नए ग्राहकों को जोड़ना, प्रतिभा का विकास, नए उत्पादों का विकास तथा कारोबार की विस्तार क्षमता को मजबूत करना शामिल है.

चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यकारी निदेशक अरुण पोद्दार ने इस साझेदारी पर कहा, ह्यह्यह निवेश हमारी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह हमारे विजन, कारोबारी मॉडल तथा दीर्घकालिक संभावनाओं पर एक अग्रणी वैश्विक वित्तीय संस्थान का भरोसा दिखाता है।

आशीर्वाद बाय आलियाक्सिस ने पटना की हिंद एजेंसी को किया सम्मानित

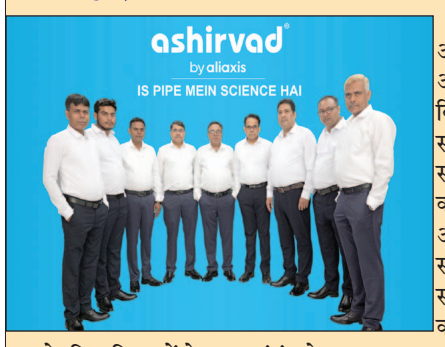

पटना। आशीर्वाद बाय आलियाक्सिस ने बिहार में अपने लंबे समय के वितरक साझेदार हिंद एजेंसी की दो दशक से अधिक पुरानी साझेदारी को सम्मानित किया। कंपनी ने कहा कि उसके लिए वितरकों के साथ संबंध केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्वास और साझा विकास पर आधारित हैं। पटना स्थित हिंद एजेंसी के प्रोपराइटर राजीव रंजन ने कहा कि आशीर्वाद के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है और उत्पादों की गुणवत्ता ने हमेशा उनका भरोसा कायम रखा है। आशीर्वाद बाय आलियाक्सिस के उपाध्यक्ष (कृषि) हरेंद्र बिष्ट ने कहा कि वितरक साझेदार कंपनी की विकास यात्रा के प्रमुख आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपने साझेदारों को सुरक्षित और सक्षम बनाने पर भी विशेष ध्यान देती है तथा भविष्य में भी इस साझेदारी को आगे बढ़ाने की उम्मीद रखती है।आशीर्वाद के पोर्टफोलियो में जल प्रबंधन से जुड़े पाइप, स्टोरेज टैंक, प्लंबिंग और कृषि संबंधी उत्पाद शामिल हैं।

हिंद एजेंसी तथा उसकी सहयोगी इकाइयां हिंद एंटरप्राइजेज और हिंद ट्रेडर्स क्षेत्र में आशीर्वाद के उत्पादों के प्रमुख वितरण चैनल के रूप में कार्य कर रही हैं। कंपनी के अनुसार, प्लंबिंग उत्पादों की मांग सबसे अधिक है और बिहार में इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी पटना से आती है।

हर हाथ में पौधा, हर दिल में हरियाली का जज्बा

सुरेश गांधी

वाराणसी। हरियाली के संकल्प ने रविवार को काशी में जन-आंदोलन का रूप ले लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के तहत जिले में एक ही दिन 15 लाख 49 हजार 600 पौधों का रोपण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से प्रेरित इस महाअभियान में अभूतपूर्व जनभागीदारी देखने को मिली। पहली बार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 146 पौधा वितरण केंद्रों से निःशुल्क पौधे बांटे गए, जहां सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ उमड़ी रही। जनपद के नोडल मंत्री एवं स्टाम्प तथा न्यायालय पंजीयन शुल्क (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री रविन्द्र जायसवाल पूरे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। उनके निर्देशन में वार्डों, प्रमुख चौराहों, तिराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए वितरण केंद्रों से महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने उत्साह के साथ पौधे लिए। कई स्थानों पर लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। घरों, विद्यालयों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण का उत्साह पूरे दिन दिखाई दिया। मुख्य कार्यक्रम केंद्रीय कारागार, शिवपुर के पीछे स्थित वीआईपी स्थल पर आयोजित हुआ, जहां नोडल मंत्री रविन्द्र जायसवाल, विधान परिषद सदस्य धर्मेन्द्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, नोडल अधिकारी एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक शम्भू कुमार, जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, वन संरक्षक रवि कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी निधि चौहान सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधारोपण किया। अपने संबोधन में रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है। वृक्षारोपण तभी सफल होगा, जब हर नागरिक पौधे को पेड़ बनने तक उसकी देखभाल का संकल्प निभाए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अधिकाधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया।

हिण्डाल्को सीएसआर ने 140 विद्यार्थियों को वितरित की शैक्षणिक सामग्री किट, शिक्षा के प्रति किया प्रेरित

रेणुकूट ,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। हिण्डाल्को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्राम गुलालझरिया स्थित आदित्य बाल विद्या मंदिर में शैक्षणिक सामग्री किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिण्डाल्को संस्थान के क्लस्टर हेड समीर नायक, क्लस्टर एचआर हेड जसबीर सिंह एवं एचआरबीपी हेड अजय सिन्हा के मार्गदर्शन तथा सीएसआर प्रमुख अनिल झा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के 140 विद्यार्थियों को निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री किट वितरित की गई।

किट में स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें, नोटबुक, लंच बॉक्स और पानी की बोतल शामिल थीं। हिण्डाल्को सीएसआर द्वारा संचालित आदित्य बाल विद्या मंदिर क्षेत्र के वंचित समुदाय के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में दुद्धी के खंड विकास अधिकारी राम विशाल चौरसिया मुख्य अतिथि तथा ब्लॉक अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम प्रधान त्रिभुवन प्रसाद यादव, पंचायत प्रतिनिधि, मुख्य ब्लॉक संयोजक हरिहर प्रसाद यादव, ब्लॉक संयोजक विश्वनाथ कुशवाहा, क्लस्टर संयोजक लक्ष्मण प्रसाद, प्रधानाचार्य सत्यनारायण, शिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि राम विशाल चौरसिया ने हिण्डाल्को सीएसआर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाई और खेलकूद दोनों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से जिज्ञासु बनने, शिक्षकों से अधिक से अधिक प्रश्न पूछने तथा मोबाइल फोन का सीमित और केवल शैक्षणिक उपयोग करने की सलाह दी। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने का आग्रह किया। हिण्डाल्को के अकाउंट्स विभाग के प्रबंधक रोहित पारीक ने विद्यार्थियों को नियमित विद्यालय आने तथा माताओं से बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। वहीं सीएसआर प्रमुख अनिल झा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाएं दीं।

सीएसआर क्षेत्र प्रमुख रमाकांत शर्मा ने कहा कि आदित्य बाल विद्या मंदिर क्षेत्र का एक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय है। उन्होंने बच्चों से शैक्षणिक सामग्री का सदुपयोग कर कड़ी मेहनत करने और अपने माता-पिता, विद्यालय तथा क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

सोनम वांगचुक का आमरण अनशन तत्काल समाप्त कराएं प्रधानमंत्री – मोहम्मद अरशद खान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का पिछले बारह दिनों से चल रहा आमरण अनशन तत्काल समाप्त कराने के लिए सरकार सकारात्मक पहल करे तथा उनकी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मांगों पर गंभीरता से विचार करे।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपनी जायज मांगों के समर्थन में आमरण अनशन करने के लिए विवश होना उचित नहीं है। सरकार का दायित्व है कि वह संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाले और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का सम्मान करे।

उन्होंने कहा कि लद्दाख की जनता लंबे समय से अपनी पहचान, संस्कृति, पर्यावरण तथा स्थानीय संसाधनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए केंद्र सरकार को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची (ट्र७३ॅ ट्टॅ४ि'ी) में शामिल करने की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि वहां के जनजातीय समुदायों के अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों, भूमि और सांस्कृतिक विरासत की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद, सहमति और संवैधानिक समाधान ही सबसे प्रभावी मार्ग हैं। सरकार को सभी संबंधित पक्षों से वार्ता कर ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे लद्दाख की जनता का विश्वास मजबूत हो और क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने इस संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाकर निष्पक्ष एवं जवाबदेह कार्रवाई करने की मांग भी की।

मोहम्मद अरशद खान ने घोषणा की कि 14 जुलाई 2026 को दोपहर 12:00 बजे उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के समर्थन में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक एकजुटता व्यक्त करेंगे तथा केंद्र सरकार से शीघ्र वार्ता कर अनशन समाप्त कराने की अपील करेंगे।

उन्होंने देशवासियों से भी आह्वान किया कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों तथा शांतिपूर्ण जनआंदोलनों के सम्मान में अपनी आवाज बुलंद करें और सरकार से आग्रह करें कि संवाद के माध्यम से लद्दाख सहित देश के सभी क्षेत्रों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।

वसई-विरार में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए विशेष महासभा बुलाने की मांग

विपक्ष नेता मनोज पाटिल ने महापौर अजीव पाटिल को लिखा पत्र

विरार। वसई-विरार शहर में 4 से 8 जुलाई के बीच हुई मूसलाधार बारिश के कारण उत्पन्न गंभीर बाढ़ की स्थिति को लेकर वसई-विरार महानगरपालिका के विपक्ष नेता मनोज पाटिल ने महापौर अजीव पाटिल को पत्र लिखकर तत्काल विशेष महासभा बुलाने की मांग की है।

मनोज पाटिल ने अपने पत्र में कहा है कि अतिवृष्टि के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, जिससे नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने और नागरिकों को स्थायी राहत मिल सके, इसके लिए इस विषय पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है। उन्होंने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 के प्रकरण-2, नियम 1 (ड) का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून के अनुसार नगर निगम के कुल सदस्यों के एक-चौथाई सदस्य अथवा स्थायी समिति के चार सदस्य लिखित मांग के आधार पर विशेष महासभा बुला सकते हैं। इसी कानूनी प्रावधान के तहत यह मांग की गई है।

मनोज पाटिल ने मांग की है कि विशेष महासभा में शहर में बाढ़ की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही वर्ष 2018 से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और आईआईटी द्वारा शहर की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर प्रस्तुत की गई तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर महानगरपालिका ने अब तक कौन-कौन से कार्य किए, उन पर कितना खर्च हुआ तथा क्या परिणाम सामने आए, इसकी विस्तृत जानकारी सदन के समक्ष रखी जाए।

इसके अलावा वर्ष 2018 से अब तक नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था, आपदा प्रबंधन की तैयारियों तथा इन कार्यों पर किए गए वार्षिक खर्च का पूरा ब्यौरा भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि वसई-विरार के नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए भविष्य में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए महानगरपालिका किस समयबद्ध कार्ययोजना पर अमल करेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी जनता को मिलनी चाहिए।

मनोज पाटिल ने महापौर से जनभावनाओं और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस विषय पर तत्काल विशेष महासभा बुलाने का आग्रह किया है।

बांद्रा-सूरत एक्सप्रेस को पालघर स्टेशन पर मिला ठहराव

पालघर। पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत सावरा के लगातार प्रयासों और रेल मंत्रालय के साथ किए गए निरंतर फॉलो-अप का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। उनकी मांग पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने ट्रेन संख्या 12935/12936 बांद्रा (टर्मिनस)सूरत एक्सप्रेस को पालघर रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

सांसद डॉ. सावरा लंबे समय से पालघर, बोईसर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन के पालघर में ठहराव की मांग कर रहे थे। उनकी पहल पर रेलवे प्रशासन ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इस मांग को स्वीकृति दे दी है।

रेलवे बोर्ड के निदेर्शानुसार यह ठहराव जल्द ही निर्धारित तिथि से शुरू किया जाएगा । फिलहाल इसे प्रायोगिक(Experimental) आधार पर लागू किया जा रहा है। इस निर्णय से पालघर, बोईसर तथा आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन मुंबई और गुजरात की ओर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली होगी।

सांसद डॉ. हेमंत सावरा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के लिए आगे भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। भविष्य में इस ठहराव को स्थायी बनाए जाने के लिए रेलवे प्रशासन पालघर स्टेशन से होने वाली टिकट बिक्री और यात्रियों की संख्या की समीक्षा करेगा।

इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद डॉ. सावरा के जनसंपर्क कार्यालय ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे इस नई रेल सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि भविष्य में इस ठहराव को स्थायी रूप से जारी रखा जा सके।

बिसांवा में पौधों का वृहद वृक्षारोपण,पूर्व ब्लॉक प्रमुख पं. सुधाकर उपाध्याय ने किया शुभारंभ

जौनपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से जनपद जौनपुर के सिकरारा क्षेत्र स्थित ग्राम सभा बिसांवा में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान प्रतिनिधि अरविंद यादव ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंडित सुधाकर उपाध्याय ने पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया।

अरविंद यादव ने पत्रकार आदेश मिश्र को जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित सुधाकर उपाध्याय ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का सबसे प्रभावी उपाय अधिक से अधिक वृक्षारोपण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसके संरक्षण का भी संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने लगाए गए पौधों की नियमित सिंचाई, खाद एवं देखभाल पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा नेता शिव शंकर तिवारी, डॉ मुन्ना पांडेय,ग्राम प्रधान अनीता यादव, पंकज सिंह, आशुतोष सिंह, वैभव सिंह, नीरज दुबे, बालक,विनोद प्रजापति, राजकुमारी, अनीता, महेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता निभाई और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूरे ग्राम सभा क्षेत्र में उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच पौधरोपण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

शिविरों में मिल रहा है आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ

नांगल। राज्य सरकार के निदेर्शानुसार शहर के नागरिकों एवं ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत पर व शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है सेवा शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा आम लोगों की समस्याओं का यथासंभव मौके पर समाधान किया जा रहा है इसी के तहत आज नांगल ग्राम पंचायत में लगे शिविर में आयुर्वेद विभाग की सेवाएं जारी रही।जानकारी देते हुए आयुर्वेद ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉ राजेंद्र कुमावत ने बताया कि आयोजित शिविर मे सोमवार को डॉ.प्रताप राम कुमावत व कंपाउडर सुमेर सिंह गुर्जर ने आयुर्वेद चिकित्सा करते हुए 61 लोगों को आयुर्वेद से लाभान्वित किया तथा 32 जनों को जीवनशैली जन्य परामर्श दिया।दूसरी तरफ शहरी सेवा शिविर के तहत नगर पालिका में आयोजित हुए शिविर में डॉ.रमेश कुमार एवं कंपाउंड विजय कुमार शर्मा ने अपनी सेवाएं दी और 10 जनों को आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ दिया गया।

जनपद के इच्छुक बी०आर०सी० 25 जुलाई, 2026 तक आवेदन करें

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया है कि कृषि विभाग, जौनपुर गोमती नदी के किनारो के ग्रामों के कृषकों को प्राकृतिक खेती से जोड़ कर उनकी आय बढाने एवं नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के लिये कृषि विभाग द्वारा खरीफ सत्र से अभियान के तहत 10 विकास खण्डों में 6875 कृषको का 55 क्लस्टर तैयार कर कार्य किया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के सफल क्रियान्यवन के लिये नेचुरल फार्मिंग के इनपुट के उत्पाद एवं आपूर्ति हेतु जैव इनपुट संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०) का चयन जिला स्तरीय गठित कमेटी द्वारा गाईड लाईन में उपलब्ध मानक के नियमानुसार किया जायेगा। जिसके लिये इच्छुक जैव इनपुट संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०) अपना आवेदन 25 जुलाई, 2026 तक उप कृषि निदेशक कार्यालय, जौनपुर को उपलब्ध कराये, ताकि जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा बी०आर०सी० का चयन कराकर क्लस्टर में शामिल कृषको को प्राकृतिक खेती से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराते हुये मिशन मोड में प्राकृतिक खेती का क्रियान्वयन कराया जा सकें।

जौनपुर जंक्शन के विकास की मांग पर मुखर हुए दिनेश टंडन,

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन ने कहा कि जौनपुर जैसे ऐतिहासिक और व्यापारिक शहर के रेलवे ढांचे को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर वाराणसी से आए उत्तर रेलवे के वाणिज्य निरीक्षक (सीएमआई) रामनिवास यादव से मुलाकात कर जौनपुर जंक्शन के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव सौंपे और उन्हें रेल मंत्री व रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आग्रह किया। दिनेश टंडन ने कहा कि जौनपुर जंक्शन पर रेलवे यार्ड, वॉशिंग सेंटर, शेडिंग सुविधा और साइडिंग रैक की व्यवस्था होने से व्यापार को नई गति मिलेगी। इससे स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ किसानों और उद्यमियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जौनपुर की जरूरतों को देखते हुए यहां से बड़े व्यावसायिक शहरों के लिए नई ट्रेनों का संचालन भी समय की मांग है। बैठक में सब्जी-फल व्यापार समिति के महामंत्री एवं प्रदेश मंत्री महेंद्र सोनकर ने जौनपुर जंक्शन पर यार्ड, वॉशिंग सेंटर और शेडिंग की सुविधा जल्द शुरू करने की मांग की। साथ ही 'मां शीतला एक्सप्रेस' नाम से जौनपुर को प्रमुख व्यावसायिक शहरों से जोड़ने वाली नई ट्रेन चलाने का सुझाव दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष

सोमेश्वर केसरवानी ने कहा कि रेलवे की उपेक्षा के कारण जौनपुर का प्रसिद्ध चमेली सुगंधित तेल उद्योग प्रभावित हुआ है। वहीं नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल और सब्जी-फल व्यापार समिति के अध्यक्ष राजमणि यादव ने जौनपुर जंक्शन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और अधिक ट्रेनों के संचालन की मांग उठाई।बैठक में संतोष अग्रहरि, छब्बूलाल सोनकर, रामकुमार साहू, सुरेश सोनकर, नरसिंह अवतार जायसवाल, रामआसरे मौर्य, रत्तीलाल सोनकर, आशीष माली, पप्पू सोनकर, बाबाजी, विजय सोनकर, राकेश जायसवाल, यशवंत साहू, चंदन जायसवाल समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।